अध्याय III: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

3.1 विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफलता के कारण राजस्व की हानि

निर्माणकार्य नियमपुस्तिका के प्रावधानों के उल्लंघन में सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी ऑफिस बिल्डिंग, कोलकाता के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹58.10 लाख के राजस्व की हानि हुई।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) निर्माणकार्य नियमपुस्तिका 2012 की धारा 12 में कहा गया है कि, पांच करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए केंद्रीय वाणिज्यिक कनसर्न की ओर से निष्पादित कार्य पर सात *प्रतिशत* की दर पर विभागीय प्रभार (डीसी) लगाया जाना और वसूल किया जाना होता है।

रिकॉर्ड की जांच से, यह देखा गया कि सीपीडब्ल्यूडी ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के कार्यालय भवन[1] का निर्माण कार्य एक ठेकेदार[2] को ₹8.30 करोड़[3] की अनुमानित लागत के प्रति ₹7.34 करोड़ के निविदा मूल्य पर सौंपा। निर्माण कार्य मई 2013 में शुरू हुआ और मार्च 2017 में ₹9.25 करोड़[4] के खर्च के बाद पूरा हुआ। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी से ₹58.10 लाख (₹8.30 करोड़ की अनुमानित लागत का 7 *प्रतिशत*) के विभागीय प्रभारों का उद्ग्रहण और वसूली करने में विफल रहा।

इकाई ने अपने उत्तर में (अगस्त 2018) कहा कि, एनएसआईसी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक संगठन है और इसलिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीसी के किसी प्रावधान को प्रारंभिक अनुमान (पीई) में नहीं रखा गया था। सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएसआईसी एक वाणिज्यिक उपक्रम है जो व्यावसायिक गतिविधियाँ करता है इसलिए एनएसआईसी से डीसी को वसूल किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, निर्माणकार्य नियमपुस्तिका के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए सीपीडब्ल्यूडी, एनएसआईसी कार्यालय बिल्डिंग, कोलकता के निर्माण पर विभागीय प्रभारों के उद्ग्रहण में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹58.10 लाख के राजस्व की हानि हुई।

---

[1] राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कार्यालय भवन (जी + 9), साल्ट लेक, कोलकाता में

[2] मैसर्स ट्रिबेनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता की करार सं.02/सीई/ईई/केसीडी-II/ 2013-14

[3] सिविल लागत ₹7.97 करोड़ + विद्युत लागत ₹0.33 करोड़

[4] ₹9.25 करोड़ = ₹8.71 करोड़ सिविल कार्य के संबंध में 27वें और अंतिम बिल + ₹0.54 करोड़, इलेक्ट्रिकल काम के संबंध में 4थेऔर अंतिम बिल

2020 की प्रतिवेदन सं. 10

मंत्रालय को यह मामला दिसंबर 2019 और मई 2020 में भी संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।